Date - 06-12-2022

Publication - Aaj (Hindi)

कोल इंडिया से सरकार को मिला 6113 रुपये का लाभांश : दीपम

सरकार को एमएसटीसी से भी 25 करोड़ रुपये का मिला लाभांश

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड और मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी) से लाभांश के तौर पर क्रमशः करीब 6113 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। वित्त मंत्रालय के निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) सचिव तुहिन कांत पांडेय ने सोमवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। दीपम सचिव के मुताबिक सरकार को कोयला मंत्रालय के कोल इंडिया लिमिटेड 6113 करोड़ रुपये और इस्पात मंत्रालय के एमएसटीसी से 25 करोड़ रुपये लाभांश के तौर पर प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार को इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी पावर ग्रिड, ऑयल इंडिया, बीईएल, मझगांव डॉक और मिधानी से करोड़ों रुपये के लाभांश मिले थे। दरअसल, दीपम के दिशा–निर्देशों के मुताबिक सीपीएसई को कर के बाद लाभ का 30 फीसदी (पीएटी) या निवल मूल्य का पांच फीसदी, जो भी अधिक हो का न्यूनतम वार्षिक लाभांश देना जरूरी है।

Date - 06-12-2022

Publication - Hindustan (Hindi)

'मिट्टी का क्षरण और पानी को रोके कोयला कंपनियां'

मिट्टी दिवस

धनबाद, विशेष संवाददाता । कोयला खनन से मिट्टी और पानी को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। गहराई तक कोयला खनन से भूगर्भ जलस्तर नीचे जाता है। वहीं खनन क्षेत्र में मिट्टी की बर्बादी होती है।

धनबाद जैसे सबसे पुराने कोयला क्षेत्र में जलस्तर की गिरती स्थिति की एक वजह कोयला खनन भी है। विश्व मिट्टी दिवस पर कोल इंडिया ने इस दिशा में पहल की बात करते हुए अनुषंगी कंपनियों को मिट्टी क्षरण रोकने के साथ-साथ जलस्तर बेहतर करने के लिए भी काम करने को कहा है। कोल इंडिया की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार किए गए कार्यों की भी जानकारी दी गई है। लिखा गया है कि कोयला क्षेत्र में घास लगाने एवं पौधरोपण की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।

कोल की सभी अनुषंगी कंपनियों में चालू वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 300 हेक्टेयर क्षेत्र में घास लगाया गया है। वहीं 1573 हेक्टेयर में पौधरापेण किया गया है।